Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

सितम्बर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड की सोनाली घोष बनी काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक 3
- मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का लोगो और वेबसाइट को किया लॉन्च 4
- उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार 4
- टिहरी के राजेश भंडारी बने वायुसेना में उप प्रमुख 5
- देहरादून-पिथौरागढ़-पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू 6
- प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार 6
- उत्तराखंड सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश 7
- उत्तराखंड के 50 हज़ार से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का होगा कायाकल्प 8
- पहाड़ों पर आधुनिक ATV वाहनों से रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस 9
- उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग 10
- उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम 11
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शुरू होगा 'हब एंड स्पोक' मॉडल 12
- विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई 12
- प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंज़ूरी 14
- सस्ती बिजली उत्पादन के लिये प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी 15
- प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू: उद्यमियों को वन टाइम नहीं, अब किस्तों में मिलेगी सब्सिडी 15
- उत्तराखंड में युवा-महिलाएँ संभालेंगी गोवंश सुरक्षा की ज़िम्मेदारी 16
- वन मंत्री ने टिहरी झील में चार दिवसीय आयोजन वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया 17
- 8वाँ दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 17
- उत्तराखंड के चार कलाकारों को मिला संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 18
- मुख्यमंत्री ने की स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत 19
- पर्यटन मंत्री ने पर्वतारोहण अभियान दल को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना 20
- मुख्यमंत्री ने 'आत्मा के स्वर' पुस्तक का किया विमोचन 22
- पैरा एशियन गेम 2022 के लिये प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन 23
- विनीता जगदीश चौधरी को मिला उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 23
- 'स्वदेश दर्शन योजना 2.0' में चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िलों को किया गया शामिल 24
- देश के श्रेष्ठ पर्यटन गाँव में पिथौरागढ़ के सरमोली का चयन 24
- प्रदेश में संविदा खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में हुई वृद्धि 26
- उत्तराखंड में चार नए सैनिक स्कूल और पाँच केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे 27
- अटल रहेंगे प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट स्कूल, सिर्फ बदलेगा बोर्ड 27
- दून में खुले देश के पहले तीन पॉलिथीन कचरा बैंक 28
- संविदा महिला व एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश 29
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोपवे निर्माण के लिये फ्राँसीसी कंपनी संग 2000 करोड़ रुपए का एमओयू किया साइन 29
- सरमोली को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार 30
- भवाली के सुबोध सहित एसएसबी के आठ सदस्यीय दल ने रुद्रगैरा पर्वत चोटी पर फतेह हासिल 31
- रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा 32
- अंतर्राष्ट्रीय रोड शो: उत्तराखंड ने किये 9000 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू 33

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड की सोनाली घोष बनी काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक

चर्चा में क्यों ?

2 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी सोनाली घोष असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) के क्षेत्र निदेशक (फील्ड डायरेक्टर) के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी सोनाली घोष ने 1 सितंबर को केएनपी के क्षेत्र निदेशक (फील्ड डायरेक्टर) के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही 118 साल पुराने केएनपी के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली सोनाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि असम सरकार ने सोनाली घोष को वन प्रमुख के पद पर तैनात करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी ने मौजूदा क्षेत्र निदेशक जतिंद्र शर्मा से पार्क का प्रभार ग्रहण किया। जतिंद्र शर्मा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

नोट :

- निदेशक बनने से पहले सोनाली घोष गुवाहाटी में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल के प्रमुख के कार्यालय में अनुसंधान शिक्षा और कार्य योजना प्रभाग की मुख्य वन संरक्षक के रूप में कार्यरत् थीं।

मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का लोगो और वेबसाइट को किया लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

2 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में उद्यमियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह इन्वेस्टर्स समिट पूरे राज्य और सभी विभाग के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- विदित है कि इसके लिये देहरादून में संवाद और 21 अगस्त को दिल्ली में इंडस्ट्री समूह के साथ बातचीत हुई है। उत्तराखंड में निवेश को लेकर उद्योग जगत् में रुचि है। इंडस्ट्री समूह के सभी लोग ब्रांड अंबेसडर हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश और नए इन्वेस्टर्स को लेकर लोग तैयार हैं। उद्योग को विस्तार के लिये उद्योग समूह तैयार हैं। राज्य में ऐसे 15 से 20 हज़ार निवेश के लिये उद्योग तैयार हैं।
- उल्लेखनीय है कि धामी सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिये 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन्वेस्टर्स समिट के लिये देहरादून से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है।

उत्तराखंड के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) द्वारा शिक्षक दिवस पर राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा के 10, माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान से 1 शिक्षक शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक, विभाग की ओर से शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी, लेकिन इन पुरस्कारों के लिये चयनित शिक्षकों को पुरस्कृत नहीं किया जा सका था।
- इन शिक्षकों में से प्रारंभिक शिक्षा में पौड़ी ज़िले से आशा बुडाकोटी, उत्तरकाशी से संजय कुमार कुकसाल, देहरादून से ऊषा गौड़, हरिद्वार से संजय कुमार, टिहरी से उत्तम सिंह राणा, चंपावत से रवीश चंद्र पंचौली, बागेश्वर से सुरेश चंद्र सती, पिथौरागढ़ से गंगा आर्य एवं नैनीताल से डॉ. आशा बिष्ट को सम्मानित किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा में उत्तरकाशी से लोकेंद्रपाल सिंह, देहरादून से संजय कुमार, पिथौरागढ़ से दमयंती चंद, बागेश्वर से त्रिभुवन चंद, अल्मोड़ा से डॉ. प्रभाकर जोशी, ऊधमसिंह नगर से निर्मल कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा।
- इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान से ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्रवक्ता डॉ. शैलेंद्र सिंह धपोला को सम्मानित किया जाएगा।

टिहरी के राजेश भंडारी बने वायुसेना में उप प्रमुख

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सीडीएस और पूर्व सेनाप्रमुख के बाद अब उत्तराखंड के टिहरी के रहने वाले राजेश भंडारी को वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राजेश भंडारी की नियुक्ति नई दिल्ली में एयरफोर्स मुख्यालय में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर हुई है।
- विदित है कि राजेश भंडारी की शिक्षा-दीक्षा देहरादून में हुई है। वे 15 दिसंबर, 1990 को एयरफोर्स में कमीशंड ऑफिसर हुए थे। उसके बाद 1 फरवरी, 2022 को एयर कमोडोर पद पर पदोन्नत हुए थे।
- इनसे पहले प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में नेल्डा गाँव निवासी एयर मार्शल विजयपाल सिंह राणा वायुसेना के उच्च पद पर पहुँचे थे। वे एयर चीफ मार्शल के सलाहकार के पद पर पहुँचने वाले टिहरी के पहले और उत्तराखंड के दूसरे ऑफिसर थे।

देहरादून-पिथौरागढ़-पंतनगर के बीच हवाई सेवा का ट्रायल शुरू

चर्चा में क्यों ?

- 4 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ के बीच प्रस्तावित हवाई सेवा के जल्द ही शुरू होने के आसार हैं। फ्लाई बिग कंपनी की ओर से हवाई मार्ग पर ट्रायल शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार फ्लाई बिग कंपनी का 19 सीटर विमान देहरादून से पिथौरागढ़ होते हुए 3 सितंबर को पंतनगर पहुँचा। इस विमान में चालक दल के अलावा पंतनगर में मौजूद कंपनी के स्टाफ के लिये ज़रूरी सामान मौजूद था।
- फ्लाई बिग प्रबंधन ने देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर एयरपोर्ट में साइट ऑफिस बनाकर कर्मचारियों की तैनाती कर दी है।
- यह माना जा रहा है कि हवाई सेवा अक्तूबर से शुरू हो सकती है। हवाई सेवा शुरू करने से पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि यह हवाई सेवा क्षेत्रीय उड़ान योजना (आरसीएस) के तहत होगी, जिसका 60 प्रतिशत किराया यात्री और 40 प्रतिशत किराया राज्य सरकार वहन करेगी।

प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिला शैलेश मटियानी पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देहरादून राजभवन में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों में प्रारंभिक शिक्षा के 10, माध्यमिक के छह और प्रशिक्षण संस्थान से एक शिक्षक शामिल हैं।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए किया गया है।
- विदित है कि शिक्षा विभाग की ओर से शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 की घोषणा इस साल फरवरी में की गई थी, लेकिन इन पुरस्कारों के लिये चयनित शिक्षकों को पुरस्कृत नहीं किया जा सका था। अब शिक्षक दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में इन शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया।
- प्रारंभिक शिक्षा में पौड़ी ज़िले से आशा बुडाकोटी, उत्तरकाशी से संजय कुमार कुकसाल, देहरादून से ऊषा गौड़, हरिद्वार से संजय कुमार, टिहरी से उत्तम सिंह राणा, चंपावत से रवीश चंद्र पंचौली, बागेश्वर से सुरेश चंद्र सती, पिथौरागढ़ से गंगा आर्य एवं नैनीताल से डॉ. आशा बिष्ट को सम्मानित किया गया।
- माध्यमिक शिक्षा में उत्तरकाशी से लोकेंद्रपाल सिंह, देहरादून से संजय कुमार, पिथौरागढ़ से दमयंती चंद, बागेश्वर से त्रिभुवन चंद, अल्मोड़ा से डॉ. प्रभाकर जोशी, ऊधमसिंह नगर से निर्मल कुमार को पुरस्कृत किया गया।
- इसके अलावा प्रशिक्षण संस्थान से ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्रवक्ता डॉ. शैलेंद्र सिंह धपोला को सम्मानित भी किया गया।

उत्तराखंड सदन में 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये सदन में 11321 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें 3530 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व और 7790 करोड़ रुपए प्रावधान का पूंजीगत मद में किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट 88728 करोड़ रुपए का हो जाएगा। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिये 77407 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था।
- विधानसभा पटल पर आए अनुपूरक अनुदान मांगों में पूंजीगत व्यय के तहत 600 करोड़ सड़कों और पुलों के निर्माण, 765 करोड़ का जल जीवन मिशन, 321 करोड़ का आवास एवं शहरी विकास, 156 करोड़ टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने के लिये भूमि अधिग्रहण, 135 करोड़ पार्किंग निर्माण में खर्च किये जाएंगें।
- इनके अलावा 128 करोड़ समग्र शिक्षा, 100 करोड़ लोनिवि की आरआईडीएफ योजना, 100 करोड़ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज निर्माण, 67 करोड़ रूफ टॉप सोलर संयंत्र व स्ट्रीट लाइट, 50 करोड़ मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन बनाने, 50 करोड़ यूनिटी माल बनाने पर खर्च किये जाएंगे।
- साथ ही खेल स्टेडियम, स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी, ऋषिकेश योग नगरी के विकास के लिये भी धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- मानसून में खस्ताहाल हो गईं सड़कों की मरम्मत के लिये 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़ खर्च होंगे। सरकार ने 284 करोड़ रुपए खाद्यान्न सब्सिडी के लिये रखा है।
- आपदा प्रबंधन के तहत 218 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

उत्तराखंड के 50 हज़ार से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का होगा कायाकल्प

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 50 हजार से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का भी कायाकल्प होगा। राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब इसका विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अमृत-एक योजना में उत्तराखंड के छह नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की के साथ ही नैनीताल को शामिल किया गया था। इन शहरों में योजना के तहत मास्टर प्लान बनाने के बाद सीवेज, पेयजल आदि के काम हुये।
- अब केंद्र सरकार अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0) की शुरुआत करने जा रहा है।
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय में इसे लेकर बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव शामिल हुये।
- उन्होंने मांग की थी कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में श्रेणी-3 के छोटे शहरों को भी शामिल किया जाए, जिस पर मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी थी। इसके बाद विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।
- राज्य के चीफ टाउन प्लानर के मुताबिक, राज्य के ऐसे 23 शहर हैं, जो कि श्रेणी-3 के हैं। श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के कुल मिलाकर 10 शहर हैं।
- अमृत 2.0 योजना के तहत शहरों का मास्टर प्लान बनेगा। इस प्लान के हिसाब से ही यहाँ सीवेज, पेयजल लाइनों के अलावा जल निकासी, ग्रीन स्पेस व पार्क विकसित किये जाएंगे। इसके लिये केंद्र सरकार से ही बजट मिलेगा।

पहाड़ों पर आधुनिक ATV वाहनों से रेस्क्यू करेगी फायर सर्विस

चर्चा में क्यों?

- 9 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड फायर सर्विस आईजी नीरू गर्ग ने बताया कि पहाड़ों के दुर्गम रास्तों तक पहुँचने के लिये फायर सर्विस के जवानों को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। इसके लिये पुलिस विभाग जल्द ही फायर सर्विस के लिये दो ऑल टेरेन व्हीकल (एटीवी) वाहन खरीदने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ये (एटीवी) वाहन खाई में उतरने, नदी, नाले सब जगह चलने में सक्षम होंगे।
- फिलहाल इन वाहनों की खरीद केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम क्षेत्र के लिये होगी। इन जगहों पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। न ही यहाँ के सँकरे रास्तों पर फायर सर्विस के छोटे रेस्क्यू वाहन पहुँच पाते हैं। ऐसे में इन जगहों के लिये एटीवी ही उपयुक्त वाहन हैं। यदि ये यहाँ सफल हो गए तो अन्य पहाड़ी स्थानों के लिये भी एटीवी खरीदे जाएंगे।
- विदित है कि फायर सर्विस आग लगने पर ही नहीं, बल्कि किसी हादसे की सूचना पर भी सबसे पहले पहुँचने वाली सेवा होती है। यही कारण है कि इसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी कहा जाता है। अभी तक फायर सर्विस के पास वाहनों का ऐसा कोई अत्याधुनिक बेड़ा नहीं है, जिससे कि दुर्गम स्थानों पर कम जोखिम के साथ आसानी से पहुँचा जा सके।
- इसके लिये पिछले दिनों फायर सर्विस की ओर से दो एटीवी वाहनों की खरीद का प्रस्ताव शासन के भेजा गया था। शासन से तो इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन अब विश्व बैंक के बजट से पुलिस को नई उम्मीद मिली है। विश्व बैंक इसके लिये जल्द बजट स्वीकृत कर सकता है। प्रत्येक वाहन की कीमत करीब 75 लाख रुपए होगी।
- ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी पहाड़ी स्थानों के लिये एटीवी की ही सिफारिश की है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी सभी पहाड़ी राज्यों को इस तरह के वाहन खरीदने को कहा है, ताकि सँकरे रास्तों पर आसानी और तेज़ी से पहुँचकर लोगों की जान बचाई जा सके।
- इन वाहनों पर आग बुझाने के लिये पानी ले जाने की सुविधा भी रहेगी, यानी ये वाहन रेस्क्यू के लिये जवानों को ले जाने के साथ-साथ आग बुझाने का काम भी करेंगे।
- आग बुझाने के लिये जान का जोखिम कम करने को फायर सर्विस जल्द ही रोबोट का सहारा भी लेगी। इसके लिये पिछले साल मंज़ूरी मिली थी। अब दो रोबोट की खरीद के लिये टेंडर भी फायर सर्विस की ओर से जारी कर दिये गए हैं। आगामी 20 सितंबर तक विक्रेताओं से बिड मांगी गई हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आधुनिक रोबोट फायर सर्विस के बेड़े में शामिल हो जाएंगे।

उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

11 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जीआई महोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में बताया कि स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिये पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतांक (जीआई) महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जल्द ही राज्य के 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी, नाबार्ड, उद्योग, सांस्कृतिक विभाग, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पर्यटन विभाग के सहयोग से महोत्सव बनाया जाएगा। जीआई महोत्सव में केंद्र सरकार की ओर से उत्पादों के प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- कृषि मंत्री ने महोत्सव में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को शामिल करने के निर्देश दिये। इसके अलावा महोत्सव में छात्र- छात्राओं को जीआई टैग से संबंधित प्रतियोगिता और रैली निकाली जाएगी।
- इस महोत्सव का आयोजन केंद्र सरकार के जीआई रजिस्ट्री विभाग की ओर से देहरादून में किया जाएगा।
- विदित है कि राज्य के तेजपात, बासमती चावल, भोटिया दन, ऐपण कला, च्यूरा ऑयल, मुन्स्यारी की राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद, थुलमा को जीआई टैग मिल चुका है।
- राज्य के जिन 18 स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा, वे हैं : मंडुवा, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, रामदाना, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, पहाड़ी तोर दाल, बुरांश शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊंनी पिछौड़ा, चमोली का मुखौटा तथा काष्ठ कला।

उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम

चर्चा में क्यों?

11 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलाव चाहते हैं। मदरसों के अपग्रेडेशन से वे भी खुश हैं।

- इसी क्रम में उत्तराखंड के चार ज़िलों में चार मदरसों को आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसा हिफजुल कुरआन कुंजाग्रांट की कमेटी ने खुद को मॉडर्न मदरसा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वक्फ बोर्ड ने मंज़ूरी दे दी है।
- इसी प्रकार वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों को चरणबद्ध तरीके से मॉर्डन मदरसा शिक्षा से जोड़ा जाएगा।
- विदित है कि एक मुस्लिम लड़की रजिया सुल्ताना ने संस्कृत में पीएचडी की है। रजिया संस्कृत में कुरान का अनुवाद कर रही है। रजिया को वक्फ बोर्ड की राज्य स्तरीय शिक्षा समिति में बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा।
- बोर्ड में पंजीकृत मदरसों को मॉडर्न किया जा रहा है। इसमें बच्चों को स्मार्ट क्लास व आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ टैबलेट व कंप्यूटर भी मुहैया कराए जाएंगे।

व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शुरू होगा 'हब एंड स्पोक' मॉडल

चर्चा में क्यों?

10 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के उप राज्य परियोजना के निदेशक प्रद्युम्न रावत ने बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 47 स्कूलों में 'हब एंड स्पोक' मॉडल शुरू होगा, जिससे इन स्कूलों के छात्र-छात्राओं की व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई की राह आसान होगी।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना के निदेशक प्रद्युम्न रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को मंज़ूरी दी गई है। इसी महीने से राज्य में यह मॉडल शुरू हो जाएगा।
- योजना के तहत जिन स्कूलों में प्रयोगशाला नहीं है, उन स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सरकार प्रयोगशाला तक आने-जाने के लिये हर साल परिवहन के लिये तीन हज़ार रुपए देगी। जबकि व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय के अलावा हर महीने छह हज़ार रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
- शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में वर्तमान में दो सौ स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों से पाँच से सात किलोमीटर की दूरी के अन्य स्कूलों के छात्र-छात्राओं को भी अब व्यावसायिक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इन स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे।
- इन सभी स्कूलों में टूरिज्म, एग्रीकल्चर, प्लंबर आदि विभिन्न आठ व्यावसायिक कोर्स चलाए जा रहे हैं।
- हब स्कूल ऐसे स्कूल हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा की प्रयोगशाला है। इन स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर भी हैं, जबकि स्पोक स्कूल, हब स्कूल के पाँच से सात किलोमीटर के दायरे में स्थित वे स्कूल हैं, जिनमें वोकेशनल ट्रेनर नहीं हैं, न ही व्यावसायिक शिक्षा की प्रयोगशाला है, इस योजना से इन स्कूलों को भी लाभ मिलेगा।

विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों?

- 12 सितंबर, 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और देहरादून में 141 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित और आधुनिक डेटा संचालित मॉडल विद्या समीक्षा केंद्र उत्तराखंड के 23.50 लाख स्कूली छात्रों के अध्ययन परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।
- विदित है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की थी। एनईपी-2020 की शुरुआत के बाद इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया है।
- उत्तराखंड में केंद्र के उद्घाटन के साथ ही, राज्य ने गुजरात शिक्षा मॉडल की तर्ज पर विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया है।
- प्रदर्शन, उपस्थिति आदि पर डेटा के अलावा दीक्षा पोर्टल की सामग्री और ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) का डेटा, राज्य की स्कूली शिक्षा पर पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

नोट :

- ज्ञातव्य है कि 21वीं सदी की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये एनईपी-2020 एक तार्किक दस्तावेज़ है।
- राज्य में 141 पीएम श्री स्कूल उत्कृष्टता हासिल करने के लिये मौजूदा स्कूलों के लिये एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय उपेक्षित बच्चों की पढ़ाई पूरी कराएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी-2020 को एक वैश्विक मॉडल के रूप में पेश किया है और सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसकी सराहना की गई है। इससे न केवल 30 करोड़ भारतीय छात्रों को लाभ होगा बल्कि पूरी दुनिया के छात्रों के लिये एक मानक स्थापित होगा।

प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
  - मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य-मैदान में 200 करोड़ रुपए, पहाड़ में 25 करोड़ रुपए।
  - योग सेंटर: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  - स्कूल: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  - यूनिवर्सिटी: मैदान में 50 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
  - डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।
- सेवा क्षेत्र नीति के अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य के औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिये औली पर्यटन विकास प्राधिकरण गठित करने की मंज़ूरी दे दी गई है।

नोट :

सस्ती बिजली उत्पादन के लिये प्रदेश में बनी पंप स्टोरेज पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

- 12 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिये राज्य सरकार पंप स्टोरेज पॉलिसी लाई है। इस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- पंप स्टोरेज पॉलिसी से राज्य की नदियों पर परियोजनाएँ लगाने वालों को जहाँ राज्य सरकार को 12.5 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं देनी होगी, वहीं उन्हें स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क, पारेषण शुल्क से भी छूट मिलेगी।
- पंप स्टोरेज पॉलिसी आने के बाद पीक समय में सस्ती बिजली मिलेगी। दिन में सौर या अन्य माध्यम से आने वाली सस्ती बिजली से पानी नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। इसके बाद रात को जब बिजली की भारी मांग (बाज़ार में महंगी बिजली) होगी, तब परियोजना से बिजली उत्पादन किया जाएगा।
- प्रस्तावित नीति में परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिये अंत:राज्यीय पारेषण शुल्क, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, निशुल्क रॉयल्टी विद्युत (12.5 प्रतिशत), भूमि पर हस्तांतरण, निकासी की त्वरित अनुमति, जल कर और सरकारी भूमि को 45 वर्षों की अवधि के लिये सर्किल दर से जुड़ी वार्षिक पट्टा दर पर आवंटित करने पर छूट दी जाएगी।
- ऊर्जा सचिव ने बताया कि नदियों पर पहले से चल रही परियोजनाओं में कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये परियोजनाएँ 45 साल के लिये होंगी, जिसके बाद राज्य सरकार के हवाले हो जाएंगी।
- नदियों पर चिन्हित क्षेत्रों में परियोजना बनाने में निजी निवेशकों का चयन टेंडर के माध्यम से होगा। वह अपने स्तर से स्थान चिन्हित करके सरकार के सामने प्रस्ताव भी ला सकते हैं।
- ऑन स्ट्रीम के साथ ही ऑफ स्ट्रीम परियोजनाएँ भी लगाई जा सकेंगी। सभी तरह की स्वीकृतियाँ मिलने के तीन साल के भीतर परियोजना का निर्माण करना होगा।
- विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड गैस की तर्ज पर अब राज्य के उधम सिंह नगर ज़िले के काशीपुर में स्थित दो गैस आधारित बिजली प्लांट के लिये आने वाली सीएनजी पर भी वैट शून्य होगा।
- इससे गैस आधारित प्लांट संचालित हो सकेंगे और प्रदेश में बिजली आपूर्ति की कमी को दूर किया जा सकेगा। इनसे बनने वाली बिजली भी सस्ती होगी।

प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू: उद्यमियों को वन टाइम नहीं, अब किस्तों में मिलेगी सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

- 13 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के नैनीताल ज़िला उद्योग महाप्रबंधक एस के. पंत ने बताया कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट पूरा होने पर वन टाइम की सब्सिडी की जगह अब किस्तों में बाँटी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- नई नीति में स्लैब में बदलाव करते हुए पाँच की जगह चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए और बी श्रेणी में पर्वतीय ज़िलों को और सी एवं डी श्रेणी में अधिकतर मैदानी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये योजना में पूंजीगत उपादान और ब्याज भी बढ़ाया गया है।
- विदित है कि अगस्त में बनी नई नीति में बड़ा बदलाव करते हुए एक करोड़ तक के निवेश में सब्सिडी सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों में दो साल के भीतर दो किश्तों में मिला करेगी। एक करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में पाँच साल के भीतर पाँच किश्तों में सब्सिडी मिलेगी।
- नया नियम यह भी है कि प्राथमिक और अति प्राथमिक श्रेणी में विनिर्माणक उद्यम नेचुरल फाइबर, एक ज़िला दो उत्पाद में चिह्नित उत्पाद, जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम, खाद्य प्रसंस्करण उद्यम में निवेशकों को अतिरिक्त पूंजी उपादान सहायता भी नियमानुसार मिलेगी।

नोट :

- इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिये अति प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत एक करोड़ में 10 लाख, एक से 10 करोड़ के बीच 15 लाख और 10-50 करोड़ के निवेश में 20 लाख अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
- ज्ञातव्य है कि पिछली औद्योगिक नीति में ए श्रेणी में (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) 40 लाख रुपया, यानी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही थी। बी श्रेणी में 35, सी श्रेणी में 30 और डी श्रेणी में 15 लाख रुपया तक सब्सिडी का प्रावधान था।
- एमएसएमई की नई नीति में ए श्रेणी में एक करोड़ रुपए तक पूंजी लगाने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का नियम बनाया गया है। एक से पाँच करोड़ रुपए तक निवेश में 50 प्रतिशत के अलावा उससे ऊपर निवेश में 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिसकी लिमिट अधिकतम 1.50 करोड़ रुपए रखी गई है। इसी श्रेणी में 5-10 करोड़ रुपए में अधिकतम ढाई करोड़ और 10 से 50 करोड़ रुपए के निवेश में अधिकतम चार करोड़ रुपए तक सब्सिडी की लिमिट रखी गई है।
- इसी तरह बी श्रेणी में एक करोड़ तक निवेश पर 40 प्रतिशत सब्सिडी, सी श्रेणी में एक करोड़ में 30 प्रतिशत और डी श्रेणी में एक करोड़ में 20 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इसके ऊपर निवेश में भी अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है

उत्तराखंड में युवा-महिलाएँ संभालेंगी गोवंश सुरक्षा की ज़िम्मेदारी

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड लोक निर्माण, पंचायती राज, शहरी विकास व पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित गोवंश के लिये गोशाला, कांजी हाउस बनाने और संचालन को लेकर हुई संयुक्त बैठक में यह निर्देश दिये गए हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में गोवंश की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी युवा-महिलाएँ संभालेंगी।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में तय हुआ कि नए एनजीओ का सत्यापन होने के बाद ही उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में गोसदनों की स्थापना व संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिसमें महिला एवं युवा स्वयं सहायता समूहों का शामिल होना सुनिश्चित किया जाएगा।
- पहले से चल रहे गोसदनों में स्थान होने पर पशुपालन, शहरी विकास, पंचायती राज विभाग आपसी समन्वय से अभियान चलाकर एक माह में सभी निराश्रित गोवंश को यहाँ पहुँचाएंगे।
- ऊधमसिंह नगर जनपद में स्थित खटीमा नगर में संचालित गोसदन में इसकी कार्रवाई सबसे पहले की जाएगी।

नोट :

- निराश्रित गोवंश के लिये वनों के पास गोसदन बनाए जाएंगे और वन विभाग से संपर्क कर बाड़ा बनाया जाएगा। गोसदनों में पशु चिकित्सा अधिकारियों की रोस्टर वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी। नए गोसदनों की स्थापना के लिये बजट ज़िलास्तर पर ज़िलाधिकारी देंगे।
- गोसदनों की स्थापना और संचालन की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट वॉट्सएप ग्रुप में अपडेट करनी होगी। मॉनिटरिंग के लिये सभी गोसदन में रिमोट सेंसिंग कैमरे लगाने होंगे। जो भी गोवंश इन गोसदनों में लाया जाएगा, उनकी तस्वीर वॉट्सएप ग्रुप में साझा करनी होगी।
- इनके संचालन को पशुपालन, शहरी विकास व पंचायती राज विभाग के विभागाध्यक्ष नोडल अधिकारी नामित होंगे।

वन मंत्री ने टिहरी झील में चार दिवसीय आयोजन वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों?

14 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश की टिहरी झील में चार दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता में कयाकिंग एवं कैनोइंग खेलों में देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु शामिल हुए हैं।
- इन खेलों से राष्ट्रीय पटल पर न केवल टिहरी की पहचान बनेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के माध्यम से राज्य के युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा।
- राष्ट्रीय स्तर के इस खेल का आयोजन करना उत्तराखंड राज्य एवं टीएचडीसी (पूर्व नाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) के लिये गौरव का विषय है।
- टीएचडीसी इंडिया के सौजन्य से आयोजित प्रतियोगिता में गोवा में होने वाले 37वें ओपन राष्ट्रीय खेलों के लिये उत्कृष्ट वरिष्ठ वर्ग के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि टिहरी झील में दूसरी बार ऐसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है।

8वाँ दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

चर्चा में क्यों?

- 17 सितंबर, 2023 को देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि 8वाँ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक सिल्वर सिटी राजपुर रोड एवं तुलास इंस्टीट्यूट में किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- फिल्म फेस्टिवल के साथ-साथ उत्तराखंड टैलेंट हंट एवं आंगन बाज़ार एग्जिबिशन का आयोजन भी किया जाएगा।
- देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजक ने बताया कि इसमें दो ग्रुप रखे गए हैं। ग्रुप में आठ से 15 साल और 16 साल से ऊपर जिसमें प्रतिभागी अपनी कला जैसे कि डांस, एक्टिंग, पोएट्री, मिमिक्री और सिंगिंग आदि का प्रदर्शन करेंगे।
- जीतने वाले प्रतिभागियों को अवॉर्ड और सर्टिफिकेट दिये जाने के साथ वोकल म्यूजिक और देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आने वाले प्रोजेक्ट में भी मौका मिलेगा।
- विदित है कि पिछले आठ वर्षों से देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता आ रहा है। जिसमें अनेक नए-नए डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर को एक प्लेटफार्म देने की कोशिश की गई है।
- उत्तराखंड से भी कई ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निकलकर आए हैं जो आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उत्तराखंड टैलेंट हंट के माध्यम से युवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने का एक प्रयास और किया जा रहा है।

उत्तराखंड के चार कलाकारों को मिला संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड

चर्चा में क्यों?

- 16 सितंबर, 2023 को देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के चार वयोवृद्ध कलाकार भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ये वे कलाकार हैं, जिन्हें पहली बार किसी राष्ट्रीय सम्मान से नवाज़ा गया है।
- सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के चार वयोवृद्ध कलाकारों में भैरव दत्त तिवारी (79) और जगदीश ढौंडियाल (78) को लोक संगीत व नृत्य में अमृत अवार्ड दिया गया। जबकि नारायण सिंह बिष्ट (75) को लोक संगीत और जुगल किशोर पेटशाली (76) को उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिये अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- अवार्ड के रूप में कलाकारों को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम के अलावा एक लाख रुपए की नकद राशि दी गई।
- इस अवसर पर उप राष्ट्रपति ने बताया कि इन कलाकारों ने अपनी संगीत विरासत की रक्षा कर युवा पीढ़ी को यही संदेश दिया है कि देश और भारतीयता से ऊपर कुछ भी नहीं। कुछ देशों की संस्कृति 500 से 600 सालों की है। लेकिन, गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति 7000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है।
- जुगल किशोर पेटशाली: ये अल्मोड़ा ज़िले के निवासी हैं। इन्होनें राजुला-मालुसाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाला मोरिया आदि पुस्तकें लिखीं।
- नारायण सिंह बिष्ट: ये चमोली ज़िले के निवासी हैं। इन्होनें उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाया।
- जगदीश ढ़ौंढियाल: ये पौड़ी गढ़वाल ज़िले के निवासी हैं। इन्होनें नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 अधिक प्रस्तुतियाँ दीं हैं।
- भैरव दत्त तिवारी: ये अल्मोड़ा निवासी हैं तथा इन्होनें कुमाऊँनी लोक परंपरा में योगदान दिया है। इन्होंनें दूरदर्शन के लिये रसिक रमोला और हारु हीत नाटकों की प्रस्तुति तैयार कीं।

मुख्यमंत्री ने की स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की। यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गाँवों में स्वच्छता की मिसाल बनने वाले नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऊधम सिंह नगर ज़िले की 15 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया।
- मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले पाँच पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया तथा 'स्वच्छता ही सेवा' गीत का भी विमोचन किया।
- इन ग्राम प्रधानों का हुआ सम्मान:
  - जनसंख्या श्रेणी 2000 से कम : नैनीताल से पस्तोला पंचायत के प्रधान खष्टी राघव, रामगढ़ बोहराकोट के बसंत लाल शाह, जमराड़ी के बलवीर सिंह, चंपावत की चौकी पंचायत के प्रधान मोहन चंद पांडे और ठांटा के प्रधान शिव शंकर पाठक को सम्मानित किया गया।
  - जनसंख्या श्रेणी 2000-5000 : नैनीताल ज़िले की किशनपुर सकुलिया पंचायत के प्रधान विपिन चंद जोशी, कनिया की सुनीता घुघतियाल, हल्दूचौड़ीग्गी के प्रधान हेमंत जोशी और देहरादून भगवानपुर जुल्हो के प्रधान दीपक जोशी को सम्मानित किया गया ।
  - जनसंख्या श्रेणी 5000 से अधिक : देहरादून के डाकपत्थर पंचायत की प्रधान मंजू, खदरी खड़क माफी की संगीता थपलियाल, हरिद्वार की खेड़ा जट की अवध कुमारी व भगेरी मेहबातपुर के प्रधान नरेंद्र कुमार और ऊधमसिंह नगर ज़िले की विगराबाग की प्रधान माधवी देवी को सम्मानित किया गया।
- ये पर्यावरण मित्र हुए सम्मानित:
  - स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिये मुख्यमंत्री ने पर्यावरण मित्र पप्पू, विनोद, शिवकुमार, मीना और सविता को सम्मानित किया।

पर्यटन मंत्री ने पर्वतारोहण अभियान दल को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 6 हज़ार 316 मीटर ऊँचे बंदरपूंछ और 6 हज़ार 512 मीटर ऊँची भागीरथी द्वितीय पर्वत श्रृंखला की चढ़ाई के लिये 12 सदस्यीय 2 दलों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया।

The Vision

In Uttarakhand Himalaya
Oct 2023

Expedition by
Development Board
and Mt. Bandarpunch (6316m)
Govt. of Uttarakhand

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद तथा भारतीय पर्वतारोहण संघ के संयुक्त तत्वावधान में इस पर्वतारोहण अभियान को अंजाम दिया जा रहा है।
- इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को स्वरोज़गार के अवसर देना है।
- पर्यटन मंत्री ने कहा कि गांसे (गौरी) और औली को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है ताकि यह पर्यटन स्थल संपूर्ण एशिया को अपनी ओर आकर्षित करे। राज्य में साहसिक पर्यटन के लिये पर्याप्त स्थान हैं। इनको विकसित करते हुए साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि नालंग-जादुंग क्षेत्र को सरकार की ओर से पर्यटन के लिये खोला जा रहा है। क्लाईमेंटाइजेशन को ध्यान में रखकर यात्रा करवाई जाए इसके लिये यात्रा को रेगुलेट करना ज़रूरी है।

मुख्यमंत्री ने 'आत्मा के स्वर' पुस्तक का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

19 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषणों के संकलन पर आधारित 'आत्मा के स्वर' पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर लघु फिल्म 'देवभूमि में कर्तव्य पथ पर 2 वर्ष' को भी प्रदर्शित किया गया।
- विदित है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हमेशा आगे बढ़कर भारत माता की सेवा की और पिछले 2 वर्ष से राज्यपाल के रूप में देवभूमि में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
- 'आत्मा के स्वर' पुस्तक राज्यपाल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों, दीक्षांत समारोह आदि के 108 प्रमुख संबोधनों का संकलन है।
- राज्यपाल द्वारा इस पुस्तक में अपने कार्यकाल के दौरान के अनुभवों को साझा किया गया है और प्रदेश के लिये 5 मिशन निर्धारित किये हैं, जो उत्तराखंड को देश में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में सहायक होंगे।

नोट :

- राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक में उनके अभिव्यक्त भावों में भारतीय सैन्य गौरव, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक एकता, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चिंतन समाहित है।
- इसके अलावा पुस्तक में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, सैन्य साहस, वीरता, नारी शक्ति का योगदान, उत्तराखंड की बेटियों की उपलब्धियाँ, आदि भी समाहित हैं।

पैरा एशियन गेम 2022 के लिये प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार चीन में 16 अक्तूबर से शुरू होने वाले पैरा एशियन गेम 2022 के लिये भारतीय टीम में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- चयनित खिलाड़ियों में राज्य के उधमसिंह नगर के कालीनगर निवासी नीलिमा राय और हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता शामिल हैं।
- ऑलराउंडर खिलाड़ी नीलिमा राय का चयन लॉन बॉल, थ्रो बॉल, तैराकी और अन्य पैरा खेलों के लिये हुआ है।
- विदित है कि नीलिमा राय ने अब तक विभिन्न स्पर्द्धाओं में 22 पदक जीते हैं।
- 'तीलू रौतेली अवॉर्ड' से सम्मानित नीलिमा राय वर्तमान में भारतीय महिला पैरा थ्रो बॉल की कप्तान हैं।
- हल्द्वानी निवासी निर्मला मेहता का चयन लॉन बॉल खेल के लिये हुआ है।

विनीता जगदीश चौधरी को मिला उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2023 को देहरादून में आईआरटीडी सभागार में आयोजित अध्यापक कॉनक्लेव में रुद्रपुर के फाज़िलपुर महरौला स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यरत् जीव विज्ञान की प्रवक्ता विनीता जगदीश चौधरी को तृतीय उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और यूसर्क के निदेशक डॉ. अनिल रावत ने विनीता को प्रशस्ति-पत्र, 11 हज़ार रुपए की नकद राशि और शॉल भेंटकर सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार राज्य के 15 शिक्षकों/शिक्षिकोओं को विभिन्न क्षेत्रों में किये गए कार्यों पर दिये जाते हैं।
- विनीता को यह सम्मान राज्य में विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में किये गए बेहतर कार्यों के चलते दिया गया है।
- वर्तमान में विनीता ब्लॉक विज्ञान समन्वयक के साथ ही ईको क्लब प्रभारी भी हैं।

'स्वदेश दर्शन योजना 2.0' में चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िलों को किया गया शामिल

चर्चा में क्यों?

- 19 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के सीमावर्ती दो जनपदों-चंपावत और पिथौरागढ़ ज़िलों को 'स्वदेश दर्शन योजना 2.0' में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और मूलभूत सुविधाओं के साथ ही इन क्षेत्रों का विकास करना है।
- योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चंपावत के ऐबटमाउंट, कोलिढेक झील, चाय बागान, चूका और ज़िला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया जाएगा।
- भारत सरकार की अधिकृत डिलायट कंपनी से आए प्रतिनिधियों को पाँचों पर्यटन स्थलों में आवश्यक सुविधाएँ, जैसे- पाथवे, कैफे निर्माण, पुस्तकालय, पार्किंग, म्यूजियम, स्थानीय शैली में निर्मित भवनों, स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु आउटलेट्स, योग एवं ध्यान केंद्र, छोटा जिम, बच्चों के मनोरंजन के संसाधन, शौचालय का निर्माण, लाइट एंड साउंड सिस्टम, बेंचेज निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, एडवेंचर पार्क का निर्माण जैसे आवश्यक कार्यों को डीपीआर में शामिल करने के निर्देश दिये गए हैं।

देश के श्रेष्ठ पर्यटन गाँव में पिथौरागढ़ के सरमोली का चयन

चर्चा में क्यों?

- 21 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के सरमोली गाँव का चयन किया है। गाँव को जल्द ही देश का श्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सूत्रों के मुताबिक, पर्यटन मंत्रालय के ग्रामीण पर्यटन भारत की नोडल अधिकारी कामाक्षी माहेश्वरी ने राज्य को पत्र जारी कर सरमोली गाँव को देश का श्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चयनित करने की सूचना दी है।
- 27 सितंबर को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। साथ ही गाँव को श्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार दिया जाएगा।
- विदित है कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी के समीप सरमोली गाँव का चयन किया गया है।
- मंत्रालय की केंद्रीय नोडल एजेंसी ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम स्टे के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 795 गाँवों के आवेदन मिले। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गाँव स्तर पर किये गए बेहतर कार्यों पर सरमोली गाँव को श्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चयनित किया गया।
- गौरतलब है कि पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी के समीप सरमोली गाँव अपनी समृद्ध संस्कृति और नैसर्गिक सुंदरता को समेटे हुए है। पर्यावरण संरक्षण के साथ गाँव के लोगों ने ग्रामीण पर्यटन को स्वरोज़गार बनाया है।

- इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन के लिये पर्यटक सरमोली गाँव आते हैं। यहाँ से हिमालय, नंदा देवी, राजरंभा, पंचाचूली, नंदा कोट चोटियों का दृश्य हर किसी को आकर्षित करता है। गाँव में होम स्टे पर्यटकों की पहली पसंद है।

प्रदेश में संविदा खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में हुई वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

- 23 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में खेल विभाग में कार्यरत संविदा खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में 78 से लेकर 140 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस आदेश के अनुसार मानदेय की संशोधित दरें 01 अक्तूबर, 2023 से लागू होंगी।
- विदित है कि खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षक वर्ष 2014 से मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
- 15 जून, 2023 को खेल मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में निदेशालय में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में मामला सामने आने के बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।
- शासनादेश के मुताबिक, अर्जुन, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ओलंपिक, विश्व कप प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ी, सैफ खेलों में पदक विजेता एवं एनआईएस से नियमित कोर्स का प्रशिक्षण डिप्लोमाधारी का मानदेय 20 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 45 हज़ार रुपए किया गया है।
- एशियाई, कॉमन वेल्थ एफ्रो एशियन, सैफ गेम्स पदक विजेता आदि का मानदेय 17 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 35 हज़ार रुपए, एशियाई कॉमन वेल्थ में एफ्रो एशियन, सैफ गेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी रहे प्रशिक्षकों का मानदेय 14 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए, सीनियर नेशनल में पदक विजेता रहे खिलाड़ी प्रशिक्षकों का मानदेय 10 से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए किया गया है।
- सीनियर वर्ग में नेशनल में प्रतिभाग और अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी प्रशिक्षकों का मानदेय 7 से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए किया गया है, जबकि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग, सीनियर नॉर्थ ज़ोन में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी रहे कोच का मानदेय 5 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 12 हज़ार रुपए किया गया है।
- इस आदेश से 210 संविदा खेल प्रशिक्षक लाभान्वित होंगे।

उत्तराखंड में चार नए सैनिक स्कूल और पाँच केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे

चर्चा में क्यों ?

- 23 सितंबर, 2023 को राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में चार नए सैनिक स्कूल और पाँच केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद शासन ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- ये सैनिक स्कूल प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जन्म स्थान पीठसैंण पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर, देहरादून और चंपावत में खुलेंगे। नए स्कूल, सैनिक स्कूल सोसायटी के तहत साझेदारी मोड में चलेंगे।
- विदित है कि प्रदेश में अभी मात्र एक सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय करता है।
- गौरतलब है कि शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक केंद्र सरकार ने देशभर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में देश में 23 नए सैनिक स्कूल को मंजूरी दे दी है। इसके बाद दूसरे चरण में सैनिक स्कूल को मंजूरी दी जानी है।
- उत्तराखंड की ओर से दूसरे चरण के लिये चार नए सैनिक स्कूल का प्रस्ताव भेजा गया है। सभी मानकों को पूरा करने एवं मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के बाद इसका प्रस्ताव भेजा गया है।
- सैनिक स्कूल के लिये ग्राम डुंगरासेठी तहसील चंपावत में 10 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जबकि ए.एन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर में 250 एकड़ एवं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूरखेड़ा देहरादून में 9.5 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
- इनके अलावा प्रदेश में पाँच नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने पांडुवाखाल तहसील चौखुटिया ज़िला अल्मोड़ा, द्वाराहाट ज़िला अल्मोड़ा, कोटद्वारा ज़िला पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्रनगर ज़िला टिहरी गढ़वाल एवं विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के मदननेगी ज़िला टिहरी गढ़वाल में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।

अटल रहेंगे प्रदेश के 189 अटल उत्कृष्ट स्कूल, सिर्फ बदलेगा बोर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को प्रदेश के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध अंग्रेजी माध्यम से चल रहे राज्य के 189 अटल उत्कृष्ट स्कूल पहले की तरह इसी माध्यम से चलते रहेंगे, लेकिन स्कूल का बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड कर दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राजकीय शिक्षक संघ की इन स्कूलों को दोबारा उत्तराखंड बोर्ड में लाने की मांग के बाद विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। इन स्कूल को लेकर अलग-अलग तीन प्रस्ताव हैं।
- पहले प्रस्ताव के अंतर्गत इन स्कूलों के बोर्ड को उत्तराखंड बोर्ड कर दिया जाएगा।
- दूसरे प्रस्ताव के अंतर्गत सीबीएसई पैटर्न को 10वीं और 12वीं के बजाय अब छठवीं कक्षा से लागू किया जाएगा तथा तीसरा, इन स्कूल में शिक्षकों की तैनाती निजी सेक्टर या अन्य से अच्छे वेतन पर की जाएगी।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है, जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा।

दून में खुले देश के पहले तीन पॉलिथीन कचरा बैंक

चर्चा में क्यों?

- 25 सितंबर, 2023 को पॉलिथीन कचरे के निस्तारण के लिये उत्तराखंड के देहरादून कैंट बोर्ड की ओर से देश के पहले तीन पॉलिथीन कचरा बैंक की स्थापना की गई है, जिनमें से एक गढ़ी स्थित कचरा बैंक का राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- दो पॉलिथीन कचरा बैंक देहरादून के गढ़ी में और तीसरा प्रेमनगर में खोला गया है।
- यह देश का प्रथम ऐसा बैंक है, जो घरों, सड़कों से गंदगी को साफ करेगा, साथ ही आमदनी का माध्यम भी बनेगा। इस बैंक से पॉलिथीन एकत्र कर आगे भेजा जाएगा, जिससे टाइल्स, बोर्ड, गमले आदि सज़ावटी सामान बनाए जाएंगे।
- इन संग्रहण केंद्रों में पॉलिथीन अपशिष्ट, जैसे- बैग, चिप्स रैपर, पैकिंग बैग, प्लास्टिक के कट्टे, ब्रेड के रैपर आदि तीन रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदे जाएंगे।
- गढ़ी में बिंदाल चौकी, डेयरी फार्म और प्रेमनगर में स्पेशल विंग में पॉलिथीन कचरा बैंक का संचालन इसी सप्ताह प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बैंक में हर माह न्यूनतम 70 टन और अधिकतम 100 टन तक पॉलिथीन कचरा खरीदने का लक्ष्य है।
- कैंट बोर्ड के सीईओ अभिनव सिंह ने कहा कि वर्तमान में पॉलिथीन बैग, चिप्स रैपर, पैकिंग बैग, प्लास्टिक के कट्टे आदि को लो वैल्यू प्लास्टिक की श्रेणी में रखा जाता है। इनका न कोई खरीदार है और न बाज़ार। कूड़ा बीनने वाले भी प्लास्टिक की बोतलें, काँच आदि को उठा लेते हैं पर पॉलिथीन बैग, चिप्स रैपर आदि नहीं लेते। पॉलिथीन कचरा बैंक इसी समस्या को सुलझाएगा।
- कैंट बोर्ड की ओर से छावनी परिषद ने सैन्य क्षेत्र की आरडब्ल्यूए (रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन) के बीच में पॉलिथीन और ई-वेस्ट कलेक्शन कंपटीशन करवाया था, जिसके विजेताओं को भी शहरी विकास मंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

संविदा महिला व एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड सरकार ने विभागों और आउटसोर्स माध्यम से संविदा, तदर्थ और नियत वेतन पर तैनात महिला और एकल पुरुष (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) कर्मचारियों को 15 दिन की बाल्य देखभाल और 120 दिनों की सीमा में बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सौगात दी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किये।

प्रमुख बिंदु

- साथ ही, ऐसे सभी एकल पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं।
- वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सरकार के इस निर्णय से 40-45 हज़ार कर्मचारियों को फायदा होगा। अस्थायी कर्मचारियों को पहली बार ये अवकाश दिये गए हैं।
- विदित है कि राज्य सरकार की नियमित महिला और एकल पुरुष कर्मचारियों को यह छुट्टियाँ पहले से मिल रही हैं।
- पितृत्व अवकाश ऐसे एकल पुरुष कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, उसकी पत्नी के प्रसवकाल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पूर्व या बच्चा पैदा होने के छह माह तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
- यह किसी अन्य अवकाश के साथ लिया जा सकेगा। सामान्यत: इस अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश ऐसी महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे- संतान की बीमारी अथवा परीक्षा के समय 18 वर्ष की आयु तक देखभाल के लिये एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अवकाश मिलेगा।
- एक बार में पाँच दिनों से कम का अवकाश मंज़ूर नहीं होगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार अवकाश मिलेगा।
- बाल दत्तक देखभाल अवकाश ऐसी महिला और एकल पुरुष कर्मचारी, जो कम-से-कम तीन वर्ष से विभाग में तैनात हों और जिन्होंने एक वर्ष की आयु तक का शिशु गोद लिया हो, को मिलेगा। गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन का अवकाश मिलेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोपवे निर्माण के लिये फ्राँसीसी कंपनी संग 2000 करोड़ रुपए का एमओयू किया साइन

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2023 को वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले लंदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोपवे निर्माण में दुनिया की अग्रणी फ्राँसीसी कंपनी पोमा के साथ उत्तराखंड में रोप-वे केबल कार निर्माण के लिये 2000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- लंदन में आयोजित हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रोड शो के ज़रिये प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित करेगी।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो में प्रदेश सरकार निवेशकों को औद्योगिक नीतियों में दी जाने वाली वित्तीय सुविधा और निवेश संभावनाओं पर प्रोत्साहित करेगी।

  दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है।
- प्रदेश सरकार निवेश के लिये ऐसे रास्तों की तलाश कर रही है, जिसमें विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे। ऐसे में रोपवे जैसे विकल्प उत्तराखंड में जहाँ एक ओर पर्यटकों को सुगमता प्रदान करेंगे। वहीं, दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ने के साथ ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी ये बेहतर सिद्ध होगा।
- विदित है कि लंदन के बाद अक्तूबर माह में सिंगापुर, ताइवान, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो होंगे।

सरमोली को मिला देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को 'राष्ट्रीय पर्यटन दिवस' के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सरमोली को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्रालय के ग्रामीण पर्यटन भारत की नोडल अधिकारी कामाक्षी माहेश्वरी ने गाँव की सरपंच मल्लिका विर्दी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान की योजना बनाई गई है। भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान के शुभारंभ के लिये 108 पर्यटक स्थानों की पहचान की। यह अभियान इन 108 स्थलों के साथ-साथ अन्य पर्यटक महत्त्व के स्थानों पर भी चलाया जाएगा।
- अभियान का उद्देश्य कूड़े की सफाई, स्वच्छता सुनिश्चित करना और एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाना और पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना है। व्यापक पहुँच के लिये, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और युवा पर्यटन क्लब (वाईटीसी) के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।
- पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सतत् विकास को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिये गए, जिनमें देशभर से 35 ग्रामीण पर्यटन गाँव क्रमशः 5, 10 और 20 गाँवों के साथ स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में शामिल थे। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के सरमोली गाँव को स्वर्ण पदक दिया गया।
- विदित है कि वर्ष 2004 में सरमोली गाँव की सरपंच मल्लिका विर्दी के मार्गदर्शन में सामुदायिक आधारित होम स्टे और प्रकृति कार्यक्रम शुरू किया गया था। मल्लिका विर्दी दो बार (2004 से 2010 और 2017 से 2022) वन पंचायत की सरपंच रहीं। उनके नेतृत्व में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने, जंगल और जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का कार्य किया गया। उन्होंने जंगल और विशेष रूप से मेसर कुंड को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये थे।
- वर्ष 2007 से मेसर वन कौतिक नामक एक लोकप्रिय वन मेले के साथ-साथ हिमाल कलासूत्र नामक एक प्रकृति और संस्कृति उत्सव आयोजित करना शुरू किया। हिमाल कलासूत्र के दौरान, पक्षी उत्सव, तितली और कीट उत्सव, पारंपरिक भोजन उत्सव, डामो नगाड़ा ढोल उत्सव, खलिया चैलेंज नामक एक नवाचारी उच्च ऊँचाई मैराथन और कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते ।

भवाली के सुबोध सहित एसएसबी के आठ सदस्यीय दल ने रुद्रगैरा पर्वत चोटी पर फतेह हासिल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के भवाली शहर निवासी फील्ड अफसर सुबोध चंदोला (53) के नेतृत्व में एसएसबी के अभियान में शामिल 7 सदस्यीय दल ने मध्य हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री से दक्षिण की ओर स्थित 5819 मीटर ऊँचाई पर स्थित माउंट रुद्रगैरा पर्वत श्रृंखला पर फतेह हासिल कर तिरंगा फहराया।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय पुलिस पदक व गृह मंत्री पदक से सम्मानित सुबोध चंदोला इससे पहले एवरेस्ट, कॉमेट, सतोपंथ, अभिगामीन, गंगोत्री वन, भगीरथी टू, त्रिशूल सहित विभिन्न पर्वत पर तिरंगा फहरा चुके हैं।
- अभियान के तहत कुल 29 सदस्यीय आरोहण दल में से 20 से ज़्यादा ट्रेनी रुद्रगैरा स्थित बेस कैंप में रुके, जहाँ से आठ पर्वतारोहियों ने आगे का सफर तय करते हुए रुद्रगैरा पर्वत चोटी पर झंडा फहराया।
- इस अभियान दल में सुबोध चंदोला के साथ ही मुख्य आरक्षी कैलाश चंद्र जोशी, आरक्षी नरेंद्र सिंह, दिलदार सिंह, प्रदीप सिंह, प्रबल प्रताप सिंह, अरविंद कुमार घाघरे, इंद्र सिंह शामिल रहे।

रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा

चर्चा में क्यों?

- 27 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रितों को स्वास्थ्य योजना के तहत असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध निदेशक के निर्देशों पर जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन लेवल 1-5 वाले कर्मचारियों, पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर को 250 रुपए प्रतिमाह, वेतन लेवल 6 वालों को 450 रुपए प्रतिमाह, वेतन लेवल 7-11 वालों को 650 रुपए प्रतिमाह और वेतन लेवल 12 के कार्मिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह अंशदान देना होगा।
- निगम से सेवानिवृत्त कार्मिक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर गोल्डन कार्ड वार्षिक अंशदान (12 माह) देकर प्राप्त कर सकते हैं।
- एकमुश्त 10 साल का अंशदान जमा कराने वाले आजीवन गोल्डन कार्ड सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
- इस संबंध में सभी मंडल प्रबंधकों को निर्देश दिये गए हैं कि गोल्डन कार्ड का फार्म भरने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों व आश्रितों का अंशदान निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

अंतर्राष्ट्रीय रोड शो: उत्तराखंड ने किये 9000 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू

चर्चा में क्यों ?

- 26-27 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय रोड शो के तहत लंदन और बर्मिंघम में दो दिन के रोड शो में निवेशकों के साथ 9000 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया है।

प्रमुख बिंदु

- 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय रोड शो के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 7000 करोड़ रुपए के निवेश पर एमओयू किया गया, जबकि पहले दिन 2000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था।
- एमओयू के लिये आयोजित बैठक में शिक्षा, पर्यटन, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न 80 उद्योग घरानों ने भाग लिया।
- औद्योगिक समूह कयान जेट के साथ दो अलग-अलग एमओयू में 4500 करोड़ रुपए और ऊषा ब्रेको के साथ 1000 करोड़ रुपए, बर्मिंघम में अलग-अलग कंपनियों के साथ 1500 करोड़ रुपए के एमओयू शामिल हैं।
- कयान जेट केबल कार प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, साथ ही औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में स्की रिसॉर्ट विकसित करने पर भी सहमति बनी है। ऊषा ब्रेको लिमिटेड हरिद्वार और अन्य जनपदों में रोपवे में निवेश करेगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन डेस्टीनेशन बनाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य में वेलनेस और ग्रामीण पर्यटन में कई संभावनाएँ हैं।
- ऋषिकेश योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यूरोप से लेकर अन्य देशों के पर्यटक हर साल बड़ी तादात में योग अध्यात्म के लिये राज्य में आते हैं। सरकार विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिये निवेशकों से बात कर रही है।